चीनी मिलों को 20 हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने की तैयारी में केंद्र सरकार

सुजय मेहदूदिया

गन्ना किसानों को बकाया दिलाने व किसान विरोधी छवि बदलने में जुटी मोदी सरकार

बेमौसम बारिश से तबाह गेहूं की सरकारी खरीद संबंधी नियम में और ढील संभव

नई दिल्ली। खेती-किसानी की समस्या को लेकर विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी कथित किसान विरोधी छवि बदलने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार किसानों के ऋण भुगतान के तरीकों में बदलाव करने और कृषि सब्सिडी देने के साथ-साथ गन्ना किसानों को भुगतान दिलाने के लिए चीनी मिलों को 20 हजार करोड़ रुपये के पैकेज देने की तैयारी कर रही है।

सूत्रों ने बताया कि पूरे देश में बेमौसम बरसात से फसलों की तबाही से किसानों के आत्महत्या करने और हाल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली में किसान गजेंद्र सिंह के आत्महत्या करने की घटना ने मोदी सरकार को अपनी नीतियों पर विचार करने के लिए विवश किया है। इस साल फरवरी में पेश आम बजट में भी किसानों या खेती-किसानी के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई थी। सूत्रों ने बताया कि कृषि की समस्या को लेकर विपक्ष और विभिन्न किसान संगठनों की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं पर सोमवार रात में प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, खाद्यान्न मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। इसमें गेहूं और गन्ना उत्पादक राज्यों के बारे में विशेष चर्चा की गई। इसमें चीनी पर आयात शुल्क 25 की जगह 40 फीसदी करने, बफर स्टॉक बनाने, लोन भुगतान के नियम में बदलाव करने, एथनॉल को बढ़ावा देने और सफेद चीनी के निर्यात पर सब्सिडी देने जैसे सुझाव पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें पंजाब में सरकारी खरीद के मसले पर विरोध प्रदर्शन और एफसीआई को उत्पाद बेचने में किसानों को हो रही दिक्कत पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि गेहूं की खरीद संबंधी नियमों में कुछ और छूट दी जा सकती है। गौरतलब है कि गन्ना उत्पादक क्षेत्रों की समस्या के संतोषजनक समाधान के लिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री की तरफ से पासवान ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। चीन उद्योग लागत से कम कीमत पर चीनी की बिक्री के कारण हो रहे नुकसान की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में चीनी उद्योग निकाय आईएसएमए ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं।

Amar Ujala
29/4/15